



2026:AHC:17689

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1053/2026

सत्यदेव @ पिंटू

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राजीव मिश्र

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव मालवीय और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री यज्ञवल्क पांडेय को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक सत्यदेव @ पिंटू की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या- 639/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिराहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद में पंजीकृत प्रकरण में, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के 03 मामलों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गिरौह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 की धारा (बी) में वर्णित किसी भी गिरौह की गतिविधियों में दुष्प्रेरण या सहायता नहीं की है। उपरोक्त मुकदमे के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने या गवाहों के साथ छेड़-छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 03.11.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मुकदमों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध किसी अन्य मामले का उल्लेख नहीं किया है।

तथ्यों की समग्रता, साक्ष्यों की प्रकृति और अभिलेख से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करते हुए, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ।

अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

आवेदक, सत्यदेव @ पिंटू को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें भयभीत करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले के आरंभ, (ii) आरोप तय होने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर गवाहों की उपस्थिति के दौरान कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (v) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

27 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।